हिन्दुस्तान 09 October 2011

बीपीएल और अंत्योदय परिवारों को राशन मिलने में होगी आसानी

लैपटॉप से होगी मॉनिटरिंग

पटना | इन्द्रभूषण

लैपटॉप से जनवितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकानों की मॉनिटरिंग होगी। इससे बीपीएल और अन्त्योदय परिवारों को राशन-किरासन मिलने में आसानी होगी। सरकार ने गरीबों को हर हाल में अनाज और किरासन सुनिश्चित कराने के लिए रोज मॉनिटरिंग करने का निर्णय किया है। यह सूचना खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मुख्यालय में भी रोज उपलब्ध रहे इसके लिए प्रखंड स्तर पर 534 कम्प्यूटर असिस्टेंट की बहाली की जा रही है।

इन कम्प्यूटर असिस्टेंटों को लैपटॉप मुहैया कराये जाएंगे। हर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी (बीएसओ) के साथ तैनात होने वाले कम्प्यूटर असिस्टेंटों, उनके लिए लैपटॉप समेत अन्य आवश्यक स्थापना खर्च के लिए105 करोड़ रुपए तय किये गये हैं। कम्प्यूटर असिस्टेंट को

प्रदेश में फ़िलहाल पीडीएस की 45 हजार दुकानें हैं। पटना जिला में सबसे अधिक तो शेखपुरा में सबसे कम पीडीएस की दुकानें है। प्रदेश के 38 जिलों में अन्त्योदय परिवारों को औसतन 87 हजार टन और अन्य बीपीएल परिवारों के लिए 1.40 लाख टन अनाज केन्द्र से मिलता है। वहीं सभी परिवारों के बीच औसतन 6.50 करोड. लीटर किरासन तेल का वितरण होता है। खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग के अधिकारी भी स्वीकारते हैं कि वितरण सिस्टम की सही मॉनिटरिंग नहीं होने से पंचायत स्तर पर गड़बड़ियों की शिकायत मिलती है। हालांकि व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कई कदम उठाये गये हैं। प्रति दिन खाद्यान्न उठाव का प्रतिवेदन मुख्यालय को भेजने, खाद्यान्न परिवहन से संबंधी ट्रकों पर जीपीएस सिस्टम लगाने और अनुमंडल पदाधिकारियों द्वारा हर महीने खाद्यान्न से संबंधित जन अदालत लगाने के निर्देश का सकारात्मक असर दिख रहा है।

दो माह में लागू होगी नई व्यवस्था

- प्रखंड स्तर पर बहाल हो रहे 534 कम्प्यूटर असिस्टेंट
- 45 हजार पीडीएस दुकानों पर रखेंगे नजर, 15 हजार मिलेगा मानदेय

25 लाख हैं अंत्योदय परिवार

अन्य बीपीएल परिवार	1.26 करोड़
अन्त्योदय परिवार को मिलता है	21 किलो चावल (3 रुपए प्रति किलो)/ 14 किलो गेहूं (2 रुपए प्रति किलो)
अन्य बीपीएल परिवार को मिलता है	15 किलो चावल (6.78 रुपए प्रति किलो) 10 किलो गेहूं (5.22 रुपए प्रति किलो)

दो महीने में यह नई व्यवस्था लागू करने की योजना है। इससे खाद्यान्न और किरासन के उठाव के साथ ही हर जरूरतमन्दों को अनाज मिलने की सूचना भी मुख्यालय स्तर पर रहेगी। इससे पीडीएस सिस्टम और मजबूत होगा। **श्याम रजक**, खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण मंत्री